Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ग्रामीण आजीविका विविधीकरण एवं आय वृद्धि में नरवा-गरूवा-घुरूवा-बाड़ी योजना के प्रभाव का अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर एवं धमतरी जिले का तुलनात्मक अध्ययन)

निशी ठाकुर* डॉ. शोभा अग्रवाल**

*** शोध छात्रा, अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत**
**** शोध निर्देशिका एवं सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत**

शोध सारांश – भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग गांवो में निवास करता है। गांवो में ग्रामीणों की आजीविका का सर्वप्रधान साधन प्रारंभ से ही कृषि रहा तथा दूसरा साधन पशुपालन। धीरे-धीरे ग्रामीण परंपराए विलुप्त होने लगी। लोग आजीविका के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे। छत्तीसगढ़ राज्य में गाँवों की पुरानी आर्थिक गतिवधियों को बचाने के लिए वर्ष 2019 में शासन द्वारा नरवा-गुरूवा-घुरूवा-बाड़ी योजना की शुरूआत की गई। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने तथा ग्रामीण परिवारों की आजीविका में स्थिरता लाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। प्रस्तुत शोध पत्र में नरवा-गरूवा-घुरूवा-बाड़ी योजना की स्थिति, उपलब्धि, समस्या एवं सुझावों को प्रस्तुत किया गया हैं। अध्ययन हेतु रायपुर एवं धमतरी जिलों के 90-90 कुल 180 हितग्राहियों से प्राथमिक समंक संग्रहण किया गया है तथा द्वितीयक समंक हेतु योजना के संचालन से संबंधित विभागों से आँकडे संग्रहित किए गए हैं। प्राथमिक समंक हेतु लाभार्थियों से आजीविका विविधीकरण, आय वृद्धि तथा महिला सशक्तिकरण पर योजना के तुलनात्मक प्रभाव का विश्लेषण किया गया हैं। परिकल्पना परीक्षण हेतु काई-स्क्वैर परीक्षण विधि का प्रयोग किया गया हैं। परीक्षण से परिणाम प्राप्त हुए है कि योजना से ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई, महिलाओं का आर्थिक लाभ मिला तथा ग्रामीणों को कृषि के अलावा आजीविका के दूसरे अवसर भी उपलब्ध हुए। रायपुर एवं धमतरी जिलों में योजना से आय वृद्धि एवं आजीविका विविधीकरण के स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर नही पाया गया हैं।

शब्द कुंजी –आजीविका विविधीकरण, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, गौठान, स्व-सहायता समूह।

प्रस्तावना – भारत देश की आत्मा गाँव में बसती हैं।देश की अधिकतम जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। प्राचीनकाल से ही गॉवों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रही हैं।ग्रामीणों की आजीविका का प्रथम साधन कृषि कार्य रहा हैं।भारत के इतिहास के विभिन्न कालों से भारत के कृषि प्रधान देश होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं।सभ्यता के विकास के साथ-साथ भारत के ग्रामीणों ने कृषि के साथ-साथ पशुपालन को अपनी आजीविका का दूसरा साधन बनाया। धीरे-धीरे विकास चक्र में आगे बढ़तें हुए देश ने औद्योगीकरण को अपनाया। जिस प्रकार किसी सिक्के के दो पहलू होते है उसी प्रकार औद्योगीकरण के भी दो पहलू सामने आए एक ओर विकास और दूसरी ओर ग्रामीणों का पलायन।ग्रामीण आजीविका के लिए कृषि एवं पशुपालन के स्थान पर उद्योगों में कार्य करने हेतु अपने गॉवों से शहरो की तरफ पलयान करने लगे।ग्रामीणों के प्रवासन से देश की पांरपरिक आर्थिक क्रियाएँ अपेक्षाकृत घटने लगी। धीरे-धीरे जनसंख्या का प्रतिशत शहरों की तरफ शून्य से बढ़ने लगा।वर्तमान में विकासशील भारत का बड़ा भाग उद्योगों पर आधारित अग्रसर होना महत्वपूर्ण है परंतु इसके साथ अपनी संस्कृति एवं परम्परा को जीवित रखना भी आवश्यक है।भारत सरकार एक ओर विकसित भारत की तरफ अग्रसर है दूसरी ओर वह अपनी ग्रामीण संस्कृति एवं प्राचीन आर्थिक परंपराओं को बचाने एवं उनके विकास के लिए तत्पर है।

भारत का राज्य 'छत्तीसगढ़' जो भारत का 26 वें क्रम का राज्य हैं। वन, खनिज, जल आदि संसाधनों की बाहुलता राज्य को देश में अलग पहचान प्रदान करता हैं। भारत का राज्य होने के कारण यहाँ की भी लगभग 78 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं कृषि कार्यो पर आधारित हैं। छत्तीसगढ विकास के आयामों को प्राप्त कर रहा है जिसके कारण राज्य की ग्रामीण जनसंख्या में पलायन एवं प्राचीन पंरपराओं का लुप्त होना देखा जा सकता हैं। वर्ष 2019 में तात्कालिक छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की ग्रामीण आर्थिक क्रियाओं को बचाने एवं विलुप्त हो रही ग्रामीण परंपराओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से सुराजी गांव योजना की शुरूआत की। सुराजी गांव योजना की शुरूआत 01 जनवरी 2019 को की गई। इस योजना के अंतर्गत चार कार्यक्रमों का संचालन किया गया नरवा-गरूवा-घुरूवा-बाड़ी। इसे सुराजी गांव योजना या नरवा-गरूवा-घुरूवा-बाड़ी योजना दोनों ही नाम से पहचान मिली। योजना का उद्देश्य जल संरक्षण, पशुधन सरंक्षण, पशुधन संवर्धन, जैविक कृषि का विकास, पोषण में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना रहा।

'छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी
नरवा-गरूवा-घुरूवा-बाड़ी
ऐला बचाना है संगवारी'

नरवा- नरवा अर्थात नाला। नरवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्षा के जल को छोटे-छोटे नाले बनाकर संरक्षित करना ताकि कृषकों को कृषि कार्य हेतु

सिंचाई के लिए पानी वर्ष पर्यंत उपलब्ध हो सके। साथ ही इस जल का प्रयोग पशु अपनी प्यास बुझाने के लिए भी कर सके।

गरूवा– गरूवा छत्तीसगढ़ी शब्द है जिसका अर्थ है पशुधन गरूवा कार्यक्रम अंतर्गत पशुधन का संरक्षण करने एवं उनका संवर्धन करने का कार्य किया गया। परंतु प्रारंभ में गरूवा कार्यक्रम अंतर्गत केवल गौवंशीय पशु अर्थात् गायों को रखा गया। कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गौठानों का निर्माण गायों के लिए डे–शेल्टर के रूप में किया गया जहाँ गायों के लिए पानी, चारा, चिकित्सा सुविधाएँ आदि की व्यवस्था की गई। गौठानो के पश्चात् शासन द्वारा गौठानों के माध्यम से प्राप्त गोबर एवं गोमूत्र के सदुपयोग एवं ग्रामीण हेतु आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से गोधन न्याय योजना की शरूआत की। योजना से ग्रामीणों को प्राप्त लाभों का विश्लेषण अध्ययन के अग्र भाग में हैं।

घुरूवा–घुरूवा का अर्थ है घरेलु अपशिष्टों की टंकी। घरों से प्राप्त होने वाले पशु अपशिष्ट एवं अन्य अपशिष्ट जैसे सब्जियों, फल आदि के छिलके, इन अपशिष्टों को घुरूवा अर्थात अपशिष्ट टंकी में डालकर टंकी को बंद कर दिया जाता है कुछ समय बाद ये अपशिष्ट जैविक खाद का रूप ले लेती है। घुरूवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैविक कृषि को बढ़ावा देना रहा। यह कार्यक्रम अपशिष्ट प्रबंधन का अच्छा मॉडल रहा। रासायनिक खाद के उपयोग का प्रतिशत योजना के माध्यम से कम करने का प्रयास किया गया हैं। इसके साथ ही जैविक खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरता भी दीर्धकाल के लिए सुरक्षित करने की भी अवधारणा से योजना संचालित की गई।

बाड़ी – बाड़ी का अर्थ है घर के अंदर या आस–पास की खेती जिसे आधुनिक क्षेत्रों में किचन गार्डन के रूप मे जाना जाता है। नरवा–गरूवा–घुरूवा–बाडी योजना के चौथे कार्यक्रम का उद्देश्य घरों में सब्जियॉ फल आदि के उत्पादन को बढ़ावा देना रहा। जिससे ग्रामीण परिवारो तक उचित पोषण पहुँच पाए तथा इन फल–सब्जियों का घरो के उपयोग के बाद शेष उत्पादन को बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकें।

योजना के संचालन से संबंधित विभाग

1. कृषि विभाग
2. जल संसाधन विभाग
3. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
4. ऊर्जा विभाग
5. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
6. पशुपालन विभाग
7. वन विभाग
8. नगरीय प्रशासन विभाग
9. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
10. उद्यानिकी विभाग

आजीविका विविधीकरण – आजीविका विविधीकरण का तात्पर्य एक व्यक्ति अथवा परिवार का आय के एक स्त्रोत पर निर्भर न रहकर अन्य स्त्रोंतो को भी अपनाना है ताकि उनकी आय मे वृद्धि हो उन्हे, अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो, आर्थिक जोखिम कम हो पाए तथा आय के एक स्त्रोत के बंद होने पर अन्य गतिविधि से आय प्राप्त हो सके।नरवा–गरूवा–घुरूवा–बाड़ी योजना ग्रामीण आजीविका विविधीकरण का एक जीवित मॉडल सिद्ध हुआ।ग्रामीणों को कृषि कार्य में सहायता के साथ–साथ अन्य आर्थिक गतिविधियों के अवसर योजना के माध्यम से प्रदान किए गए।

अध्ययन की आवश्यकता– आजीविका विविधीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम माना जाता है। ग्रामीण आजीविका विविधीकरण के अवसरों को समझने के लिए नरवा–गरूवा–घुरूवा–बाड़ी योजना का अध्ययन आवश्यक हैं। अध्ययन के माध्यम से योजना के लाभार्थियो को मिलने वाले लाभों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इस योजना के संबंध में शोध कार्य अन्य विकास योजनाओं तुलना में कम हुए है अत: योजना की सफलता अथवा असफलता की वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए इस विषय पर अध्ययन की आवश्कता है।

अध्ययन का योगदान– प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर संभाग में नरवा–गरूवा–घुरूवा–बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीण आजीविका विविधीकरण तथा आय में वृद्धि की वास्तविक स्थिति का मूल्याकंन प्रस्तुत करता है। अध्ययन में योजना के क्रियान्वयन के समय आ रही समस्याओं को भी प्रस्तुत किया गया है। इन समस्याओं के सुझाव भी प्रस्तुत किये गये है। ग्रामीण आजीविका अथवा आर्थिक विकास से संबंधित सरकार के किसी भी प्रयास को मार्गदर्शन प्रदान करने की कोशिश की गई है। वर्तमान में नरवा–गरूवा–घुरूवा–बाड़ी योजना बंद कर दी गई है परंतु अध्ययन के माध्यम से इस योजना को पुन: प्रांरभ करने का सुझाव दिया गया है साथ ही पुन: प्रारंभ करने पर योजना के संबंध मे किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए इस पर भी अध्ययन के द्वारा प्रकाश डाला गया है।

संबंधित शोध साहित्य का पुनरावलोकन

1. **गुप्ता अरूणेश कुमार (2021)** ने अपने शोध पत्र **'छत्तीसगढ़ राज्य की नरवा–गरूवा–घुरूवा –बारी योजना'** में बताया कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या के लिए नरवा–गरूवा– घुरूवा–बारी योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है इन कार्यक्रमों के माध्यम से भू–जल रिचार्ज, सिंचाई की उपलब्धता एवं जैविक कृषि के विकास में सहायता प्राप्त हो रही है। योजना के माध्यम से किसानों को दोहरी फसल लेने में आसानी हो रही है। पशुओं की उचित देखरेख संभव है। लेखक के अनुसार इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आयेंगी तथा पोषण में सुधार होगा। लेखक ने बताया कि यह प्रथम कार्यक्रम है जिसमें दिनचर्या को रोजगार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन निश्चित ही प्रदेश के अर्थव्यवस्था एवं जीवनस्तर में वृद्धि करेगा।

2. **कुमार एस. एवं सारस्वत सपना शर्मा (2021)** ने अपने शोध पत्र **'ग्रामीण समाज में सुराजी गाँव (नरवा–गरूवा–घुरूवा–बारी) योजना के प्रभाव का अध्ययन (छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के संदर्भ में)'** में नरवा– गरूवा–घुरूवा–बाड़ी योजना के महत्व को बताते हुए योजनांतर्गत ग्रामीण संस्कृति के पुनर्जीवन को बताया हैं। उनके अनुसार इस योजना से कृषि को बढ़ावा मिल रहा है साथ ही साथ ग्रामीणों के स्वरोजगार में वृद्धि हो रही है एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा हैं।

3. **Mathur Parul (2021)** ने अपने शोध–पत्र **'Narwa, Garuwa, Ghuruwa, Baadi (NGGB) Program Development of Chhattisgarh' (2021)** में एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन में नरवा–गरूवा–घुरूवा–बाड़ी की भूमिका को समझाया हैं। लेखक के अनुसार एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन में राज्य की यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन का तात्पर्य ऐसे समन्वित प्रबंधन से है जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहें, लोगों की आजीविका चलती

रहे, जैवविविधता बनी रहे तथा प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग होता रहा। प्रस्तुत शोध-पत्र में लेखक ने नरवा-गरूवा-घुरूवा-बाड़ी को इसी परिदृश्य से जोड़ते हुए इन चारों कार्यक्रमों का महत्व स्पष्ट किया है।

4. Das Piyush (2022)द्वारा अपने शोध पत्र **'A Revolution ofApproval of Model NGGB in RuralAreas of Chhattisgarh'** में छत्तीसगढ़ राज्य की नरवा-गरूवा-गरवा-बाड़ी योजना के क्रियान्वयन मॉडल, चुनौतियो, परिणाम तथा योजना का राज्य के ग्रामीण विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया हैं। लेखक के अनुसार योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, पशुधन संवर्द्धन, अपशिष्ट प्रबंधन तथा पोषण सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार एवं विकास हेतु एक विशेष मॉडल है। चारो घटकों के एकीकृत विकास से ग्रामीण विकास संभव हैं।

5. Kumar Siddharth,A.K. Gauraha, Sharma ShashankAnd Bhaskar Shiv (2021) ने अपने शोध पत्र **'An EconomicAnalysis of vermicompost in Balod District of Chhattisgarh'** में बालोद जिले के तीन ब्लॉक के वर्मी कम्पोस्ट स्वयं सहायता समूहों से समंकों का संकलन कर वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन के संसाधनों और उनके विपणन संबंधी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर, वर्मी कम्पोस्ट के विपणन में आने वाली समस्याओं को दर्शाया है साथ ही उन समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं।

6. साहू तोमेश्वरी (2025) ने अपने शोध-पत्र **'छत्तीसगढ़ की सुराजी गाँव योजना अंतर्गत गरूवा योजना की भूमिका का अध्ययन'** में सुराजी गाँव योजनांतर्गत संचालित गरूवा कार्यक्रम की उपयोगिता को बताया है। उनके शोध-पत्र में गरूवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन, चुनौतियाँ, समस्याएँ एवं सुझावों को दर्शित किया है। उनके अनुसार यह योजना ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. नरवा-गरूवा-घुरूवा-बाड़ी योजना के लाभार्थियों में आजीविका विविधीकरण की स्थिति का अध्ययन करना।
2. योजना के परिणामस्वरूप ग्रामीणों की आय में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करना।
3. योजना के दौरान लाभार्थियों को प्राप्त आजीविका विविधीकरण के अवसरों का मूल्याकंन करना।
4. योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में हुए सुधार का मूल्याकंन करना।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध पत्र हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों समंको का प्रयोग किया गया हैं। प्राथमिक समंक हेतु रायपुर संभाग अंतर्गत रायपुर एवं धमतरी जिलों से 180 हितग्राहियो से साक्षात्कार के माध्यम से प्रश्न कर समंको का संकलन किया गया है। साथ ही द्वितीयक समंक संकलन के लिए योजना से संबंधित विभागों के प्रतिवेदन, रिसर्च जर्नल्स एवं इंटरनेट का प्रयोग किया गया हैं।

शोध का प्रकार- प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रकार वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध हैं।

समंक संकलन की विधि- आँकड़ों के संकलन हेतु सरल यादृच्छिक नमूना विधि का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण की विधि- काई स्क्वैर टेस्ट विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध अभिकल्प

समग्र: रायपुर एवं धमतरी जिले में नरवा-गरूवा-घुरूवा-बाड़ी योजना के हितग्राही

प्रतिदर्श विधि: यादृच्छिक नमूना विधि

प्रतिदर्श आकार: 180 (रायपुर से 90 एवं धमतरी से 90)

सर्वेक्षण क्षेत्र: रायपुर एवं धमतरी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

H_1 नरवा-गरूवा-घुरूवा-बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई है।

H_2 योजना के माध्यम से प्राप्त आजीविका विविधीकरण के अवसरों में रायपुर तथा धमतरी जिलें में अंतर हैं।

H_3 नरवा-गरूवा-घुरूवा-बाड़ी योजना ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हैं।

अध्ययन की सीमाएँ :

1. आजीविका विविधीकरण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं अथवा सरकारी प्रयासों में से नरवा-गरूवा-घुरूवा-बाड़ी योजना का चयन किया गया हैं।
2. छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में से दो जिले रायपुर एवं धमतरी का चयन अध्ययन हेतु किया गया हैं।
3. रायपुर एवं धमतरी योजना के विभिन्न हितग्राहियों मे से कुल 180 हितग्राहियों का चयन किया गया हैं।
4. समंक संकलन पूर्णत: हितग्राहियों की स्वयं की जानकारी पर आधारित है जिसमें कभी - कभी अपूर्ण जानकारी की संभावना बनी रहती हैं।
5. योजना के मूल्याकंन हेतु योजना अवधि 4.11 माह के समंकों का विश्लेषण किया गया हैं।

नरवा कार्यक्रम से आजीविका विविधीकरण - नरवा कार्यक्रम का उद्देश्य जलस्त्रोंतों का संरक्षण एवं उन्हे पुनर्जीवित करना रहा। योजनावधि में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 37109 नरवा का निर्माण किया गया। नरवा के माध्यम से ग्रामीणों को आजीविका के अवसर प्राप्त हुए वे निम्नलिखित हैं

1. सिंचाई उपलब्ध होने के कारण कृषक केवल खरीफ फसल पर निर्भर न रहकर रबी की फसलों की खेती भी कर पाए।
2. वर्ष पर्यंत पानी की उपलब्धता पशुपालन गतिविधियों को बढ़ाने में उपयोगी रही जिससे दुग्ध व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि हुई।
3. छोटे नहरों में पानी संग्रहण से ग्रामीणों को मतस्य पालन गतिविधि के भी अवसर प्राप्त हुए।
4. रबी एवं खरीफ की फसलों के जल उपलब्धता ने कृषकों को सब्जी, मसाला, फल एवं फूलों की खेती जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन से कृषकों को आजीविका विविधीकरण के सुअवसर प्राप्त हुए जिससे उन्हे अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई।
5. नरवा कार्यक्रम केवल कृषक अपितु ग्रामीणों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार प्राप्त कराने में भी सहायक रहा।नरवा निर्माण हेतु महात्मागांधी रोजगार गांरटी के अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार की प्राप्ति हुई।

तालिका क्रमांक - 1: रायपुर एवं धमतरी जिले में नरवा की स्थिति

क्र.	जिला	स्वीकृत नरवा की संख्या	पूर्ण नरवा की संख्या	प्रतिशत
1.	रायपुर	5652	5652	100%
2.	धमतरी	446	99	22.19%
	योग	**6098**	**5751**	

(स्त्रोत:- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

ग्राफ क्रमांक - 1

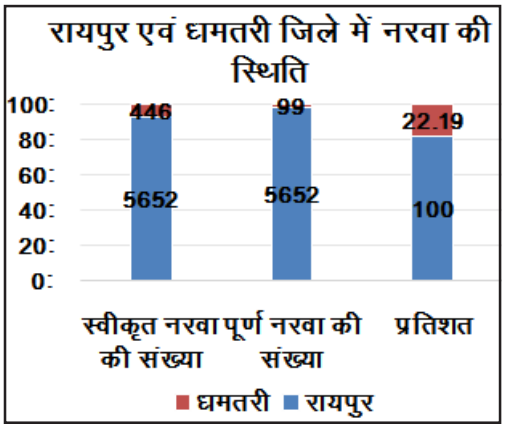

तालिका क्रमांक 1 में रायपुर एवं धमतरी जिले में स्वीकृत नरवा संचरना के विरूद्ध पूर्ण की गई नरवा संरचना का प्रदर्शित किया गया हैं। रायपुर जिले में 5652 नरवा संरचना निर्माण हेतु स्वीकृत की गई थी तथा 5652 (100 प्रतिशत) नरवा निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया। वहीं धमतरी जिलें में 446 स्वीकत की गई संरचनाओं में से केवल 99 नरवा निर्माण पूर्ण किया गया जो कि स्वीकृत का 22.19 प्रतिशत था। इस प्रकार रायपुर जिले में धमतरी जिले की तुलना नरवा निर्माण का कार्य अधिक रहा।

गरूवा कार्यक्रम से आजीविका विविधीकरण - गरूवा कार्यक्रम पशुधन संरक्षण एवं पशु संवर्धन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। ग्रामीणों को कृषि कार्य के अतिरिक्त पशुपालन से आजीविका के अवसर प्राप्त हुए। पशुपालक, चरवाहे, महिला स्व सहायता समूह, कृषक एवं उद्यमी गरूवा कार्यक्रम के हितग्राही रहे। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गौठान निर्माण किया गया। गौठानों में पशुओं विशेषकर घुमंतु पशओं को संरक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण को आजीविका के विभिन्न अवसर प्राप्त हुए जिसका विश्लेषण अग्रलिखित हैं:

1. गौठानों के माध्यम से चरवाहों कों अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई।
2. राज्य में कुल 1,62,497 पशुपालक कार्यक्रम से लाभान्वित हुए।
3. गौठान निर्माण हेतु मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को रोजगार की प्राप्ति हुई।
4. 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों एवं पशुपालको से 2 रू. प्रति कि.ग्रा. की दर से गोबर का क्रय किया गया। गोबर विक्रय कर पशुपालकों को आय का अतिरिक्त अवसर प्राप्त हुआ।
5. क्रय किए गए गोबर को स्व सहायता समूहों को दिया जाता हैं इन समूहों में सदस्य महिलाएँ होती थी। समूह की महिलाएँ गोबर से पेंट, डिस्टेंपर, खाद एवं गोबर के अन्य उत्पाद जैसे दिया, अगरबत्ती, लकड़ी आदि बनाकर स्वयं में उद्यमिता का विकास करने में सफल रही साथ ही इन उत्पादों को बेचकर महिला अजीविका एवं आय का अवसर प्राप्त कर पाई।
6. गोबर के सफल उपयोग के बाद शासन ने पशुपालकों से गौ-मूत्र क्रय किया। 4 रू. प्रति लीटर की दर से खरीदे गए गौ-मूत्र से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा कीटनाशक एवं वृद्धिवर्धक का निर्माण किया। इसके लिए उन्हे प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। कीटनाशक एवं वृद्धिवर्धक का विक्रय ग्रामीण महिलाओं की आजीविका विविधीकरण एवं आय वृद्धि का सक्षम साधन बनी।
7. गौठानों मे शासन द्वारा महात्मागांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) की शुरूआत की जिसके अंतर्गत ग्रामीणों एवं स्व सहायता समूहों को घरेलू उत्पाद जैसे अगरबत्ती, रेडी टू इट फूड, बिस्किट, साबुन, पापड, अचार आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इससे ग्रामीणों को आय का अतिरिकत साधन एवं आजीविका के अवसर प्राप्त हुए। रीपा कार्यक्रम से 11608 हितग्राही योजना काल में लाभन्वित हुए।

तालिका क्रमांक - 2: गौठान निर्माण की स्थिति एवं सड़कों से गौठानों में विस्थापित पशुओं की स्थिति (रायपुर एवं धमतरी जिले की तुलना)

क्र.	जिला	गौठान निर्माण		पशुओं का गौठानों में विस्थापन
		स्वीकृत	पूर्ण	
1.	रायपुर	344	344	10803
2.	धमतरी	312	312	289
	योग	**656**	**656**	**11092**

(स्त्रोत:- गोधन न्याय योजना समीक्षा प्रतिवेदन-2023 कृषि विभाग छ.ग.)

ग्राफ क्रमांक - 2

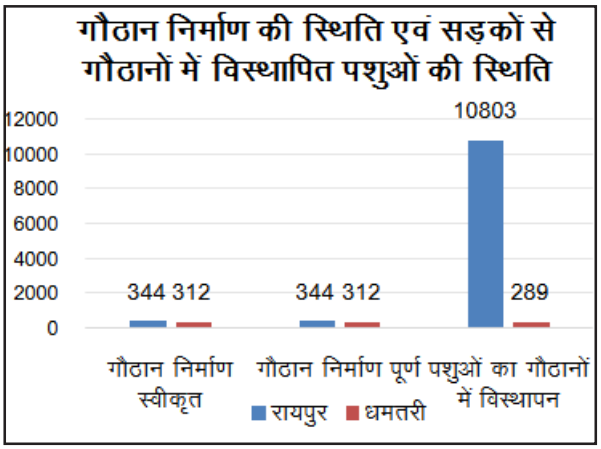

उक्त तालिका क्रमांक 2 के अनुसार रायपुर जिले में 344 स्वीकृत गौठानों में से 100 प्रतिशत गौठानों का निर्माण पूर्ण हुआ उसी प्रकार धमतरी जिले में भी स्वीकृत गौठानों के विरूद्ध 100 प्रतिशत गौठानों का निर्माण पूर्ण किया गया। वही सड़को से गौठानों में विस्थापित पशुओं (गायों) की संख्या रायपुर जिले में 10809 थी जबकि धमतरी जिले में इनकी संख्या 289 थी।

तालिका क्रमांक - 3: गोबर क्रय एवं गोबर से उत्पादित कम्पोस्ट की स्थिति (रायपुर एवं धमतरी जिले की तुलना)

क्र.	जिला	गोबर क्रय (क्वि. में)	उत्पादित कम्पोटस्ट (क्वि. में)	कम्पोस्ट का विक्रय (क्वि. में)	उत्पादन की तुलना में विक्रय
1.	रायपुर	754528	237475	212542	90%
2.	धमतरी	518760	139766	125808	90%
	योग	**1273288**	**377241**	**338350**	

(स्त्रोत – गोधन न्याय योजना समीक्षा प्रतिवेदन–2023 कृषि विभाग छ.ग.)

ग्राफ क्रमांक – 3

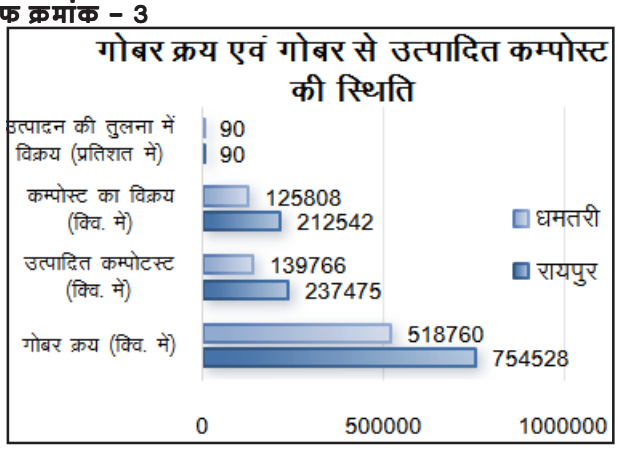

तालिका क्रमांक 3 में रायपुर एवं धमतरी जिलों में गोबर क्रय तथा गोबर से निर्मित कम्पोस्ट एवं उनके विक्रय की तुलना की गई हैं। रायपुर जिले में 754528 क्वि. गोबर क्रय कर महिला स्व–सहायता समूह के माध्यम से 237475 क्वि. कम्पोस्ट तैयार किया गया जिसमें से 90 प्रतिशत कम्पोस्ट का विक्रय 6 रू. प्रति क्वि.ग्रा. की दर से विक्रय कर अतिरिक्त आय प्राप्त की गई। वही धमतरी जिले में 518760 क्वि. गोबर क्रय से 139766 क्वि. कम्पोस्ट तैयार किया गया जिसमें से 90 प्रतिशत कम्पोस्ट का विक्रय कर महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा आय प्राप्त की गई।

तालिका क्रमांक – 4 : गोबर से प्राकृतिक पेंट, डिस्टेपर, उत्पादन एवं विक्रय की स्थिति (रायपुर एवं धमतरी जिले की तुलना)

(राशि रू में)

क्र.	जिला	संचालित पेंट इकाई	पेंट व डिस्टेंपर का उत्पादन (लीटर में)	पेंट व डिस्टेंपर का विक्रय (लीटर में)	विक्रय से प्राप्त शुद्ध आय
1.	रायपुर	3	48242	32116	4343550
2.	धमतरी	10	5589	3500	193810
	योग	**13**	**53831**	**35616**	**4537360**

(स्त्रोत:– गोधन न्याय योजना समीक्षा प्रतिवेदन–2023 कृषि विभाग छ.ग.)

ग्राफ क्रमांक – 4

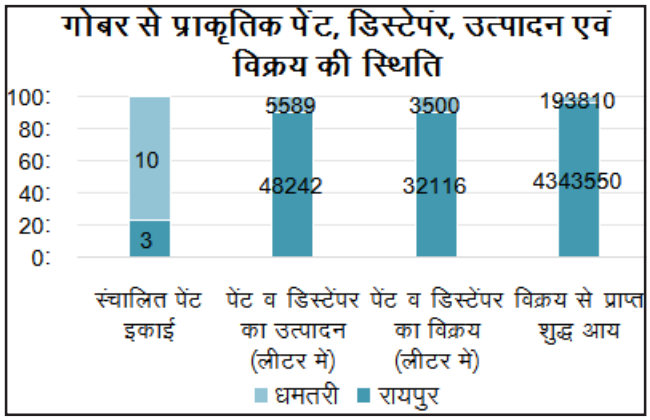

तालिका क्रमांक 4 में रायपुर एवं धमतरी जिलों में पेंट इकाईयों, पेंट, डिस्टेपंर के उत्पादन, विक्रय तथा विक्रय से आय को दर्शाया गया है रायपुर जिले में संचालित 3 पेंट इकाईयों में कुल 48242 लीटर पेंट–डिस्टेंपर का उत्पादन कर 32116 लीटर तथा डिस्टेंपर का विक्रय किया गया। विक्रय से रायपुर जिले की पेंट इकाईयों के संलग्न महिलाओं द्वारा 43,43,550 रू. की शुद्ध आय अर्जित की गई। जबकि धमतरी जिले में 10 इकाईयां संचालित होने के बाद भी 5589 लीटर पेंट–डिस्टेंपर का उत्पादन किया गया जिसमें से 3500 लीटर विक्रय कर कुल 193810 रू. की शुद्ध आय अर्जित की गई।

तालिका क्रमांक – 5: गो–मूत्र क्रय एवं गो–मूत्र से कीटनाशक तथा वृद्धिवर्धक क्रय–विक्रय की स्थिति (रायपुर एवं धमतरी जिले की तुलना)

(राशि रू में)

क्र.	जिला	गो–मूत्र क्रय (लीटर में)	कीटनियंत्रक एवं वृद्धिवर्धक उत्पादन (लीटर में)	कीटनियंत्रक एवं वृद्धिवर्धक विक्रय (लीटर में)	विक्रय से प्राप्त आय
1.	रायपुर	6825	2930	2919	145390
2.	धमतरी	3975	2843	2174	134310
	योग	**10800**	**5773**	**5093**	**279700**

(स्त्रोत:– गोधन न्याय योजना समीक्षा प्रतिवेदन–2023 कृषि विभाग छ.ग.)

ग्राफ क्रमांक – 5

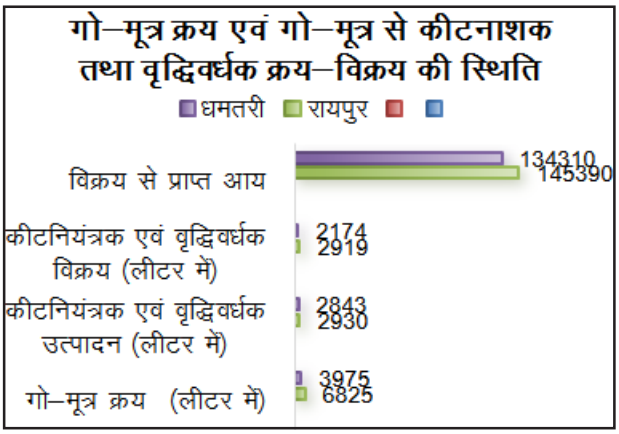

तालिका क्रमांक 5 के अनुसार रायपुर जिले में पशुपालकों (गौपालकों) से कुल 6825 लीटर गो–मूत्र क्रय किया गया जबकि धमतरी जिले में इस क्रय की मात्रा 3975 लीटर थी। क्रय किए गए गौ–मूत्र से महिला स्व सहायता समूहों ने कीटनाशक एवं वृद्धिवर्धक का उत्पादन कर विक्रय किया गया। रायपुर जिले में 2930 लीटर कीटनाशक तथा वृद्धिवर्धक का उत्पादन किया गया जिसमें से 2919 लीटर का विक्रय कर कुल 1,45,390 रू. की आय महिला स्व सहायता समूह द्वारा अर्जित किया गया। जबकि धमतरी जिले में समूह की महिलाओं ने 2843 लीटर कीटनियंत्रक एवं वृद्धिवर्धक के उत्पादन में से 2174 लीटर का विक्रय कर 134310 रू. की आय अर्जित की। धमतरी की तुलना में रायपुर जिले में गो–मूत्र आधारित आय अधिक रही।

घुरूवा कार्यक्रम से आजीविका विविधीकरण – घुरूवा कार्यक्रम का उद्देश्य जैविक खाद के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा देना था। जिसमें ग्रामीणों के आय में वृद्धि के साथ पोषण भी उपलब्ध है। घुरूवा कार्यक्रम

द्वारा ग्रामीणों में आजीविका विविधीकरण को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता हैं:

1. घुरूवा कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों के घरो में घुरूवा निर्माण कर घुरूवा के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा जैविक खाद का उत्पादन किया गया इस खाद का प्रयोग स्वयं की भूमि में करने के पश्चात् शेष खाद का विक्रय कर ग्रामीणों में अपनी आजीविका में वृद्धि की।
2. जैविक खाद के उपयोग से कृषि लागत में 25-30 प्रतिशत की कमी आई जिससे यह बचत कृषकों की अतिरिक्त आय बनी।
3. महिला स्व-सहायता समूहों को जैविक उत्पाद आधारित उद्यम चलाने के अवसर प्राप्त हुए।
4. घुरूवा निर्माण कार्य में मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार की प्राप्ति हुई।

तालिका क्रमाक - 6: घुरूवा उन्नयन, जैविक खाद उत्पादन एवं उपयोग की स्थिति (रायपुर एवं धमतरी जिले की तुलना)

क्र.	जिला	प्रस्तावित घुरूवा	पूर्ण घुरूवा	कुल उत्पादित जैविक खान (टन में)	स्वय की भूमि में उपयोग जैविक खाद (टन में)
1.	रायपुर	30,000	29,504	53,250	53250
2.	धमतरी	4038	130	5	5
	योग	**34038**	**29634**	**53255**	**53255**

(स्त्रोत:- गोधन न्याय योजना समीक्षा प्रतिवेदन-2023 कृषि विभाग छ.ग.)

ग्राफ क्रमांक - 6

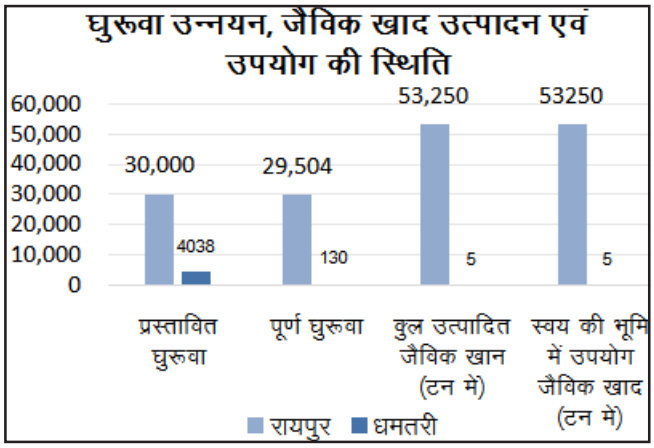

उक्त तालिका क्रमांक 6 में रायपुर एवं धमतरी जिले में घुरूवा निर्माण की स्थिति तथा घुरूवा से उत्पादित जैविक खाद की स्थिति प्रर्दशित की गई हैं। रायपुर जिले में 30,000 स्वीकृत घुरूवा सरंचना में से 29,504 घुरूवा निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया। जो स्वीकृत की तुलना में 98.34 प्रतिशत था वही धमतरी जिले में 4038 प्रस्तावित घुरूवा संरचना के विरूद्ध 130 घुरूवा निर्माण पूर्ण किया गया जो स्वीकृत का केवल 3.21 प्रतिशत था। घुरूवा में उत्पादित जैविक खाद की मात्रा रायपुर जिले में 53250 टन तथा धमतरी जिले में केवल 5 टन रही। उत्पादित खाद का 100 प्रतिशत उपयोग रायपुर एवं धमतरी जिले मे ग्रामीणों द्वारा स्वयं की भूमि में किया गया।

बाड़ी कार्यक्रम से आजीविका विविधीकरण - बाड़ी अर्थात घरेलु खेती/ बाड़ी कार्यक्रम के तहत ग्रामीण परिवारों में बाड़ी उन्नयन कराकर पोषण उपलब्ध कराया जाता है प्रतिवर्ष 1,00,000 बाड़ियों का विकास का लक्ष्य राज्य द्वारा रखा जाता हैं।बाड़ी कार्यक्रम तहत सब्जियों का उत्पादन वर्ष पर्यंत ग्रामीणों द्वारा किया जाता हैं जिससे उन्हें पोषण तो मिलता ही है साथ ही अतिरिक्त सब्जियों के विक्रय से ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती हैं।

1. सब्जियों के साथ मौसमी फल, औषधीय पौधे, मसाले एवं फूल आदि के उत्पादन से आय के स्त्रोत प्राप्त हो रहे हैं।
2. बाड़ी के माध्यम से सब्जी, फूल आदि के पौधे तैयार कर नर्सरी से आय अर्जित की गई।

तालिका क्रमाक - 7: बाड़ी विकास एवं बाड़ियों से औसत आय की स्थिति (रायपुर एवं धमतरी जिले की तुलना)

क्र.	जिला	वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25		
		बाड़ी संख्या	वितरित पौधो की संख्या	औसत आय प्रति बाड़ी (रूपए में)	बाड़ी संख्या	वितरित पौधो की संख्या	औसत आय प्रति बाड़ी
1.	रायपुर	3700	43894	2450	3700	97464	2900
2.	धमतरी	4500	45677	3100	4573	61430	4400
	योग	**8200**	**89571**	**-**	**8273**	**58894**	**-**

(स्त्रोत:- गोधन न्याय योजना समीक्षा प्रतिवेदन-2023 कृषि विभाग छ.ग.)

ग्राफ क्रमांक - 7

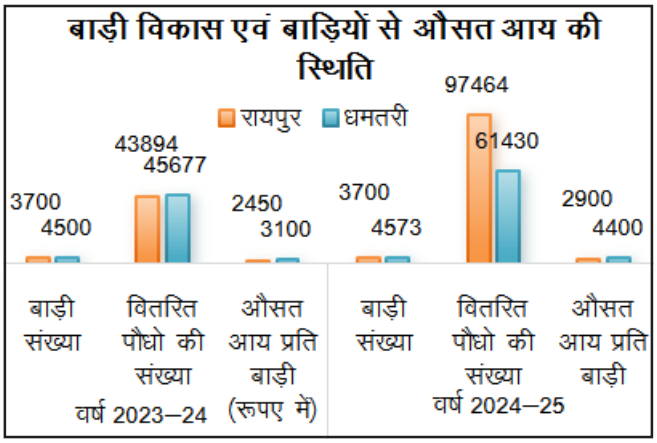

तालिका क्रमांक 7 में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में रायपुर तथा धमतरी जिले में बाड़ी की संख्या, उन बाड़ियों में वितरित किए गए पौधों की स्थिति तथा प्रति बाड़ी औसत आय को दर्शाया गया हैं। वर्ष 2023-24 में रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों मे 3700 बाड़ियों तथा धमतरी जिले में 4500 बाड़ियों का उन्नयन किया गया। रायपुर जिले की बाड़ियों में वितरित किए गए पौधों की संख्या 43894 तथा इन बाड़ियों की औसत आय 2450 रू. रही जबकि धमतरी जिले में वितरित किए गए पौधो की संख्या 45677 थी और प्रति बाड़ी औसत आय 3100 रू थी। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में रायपुर एवं धमतरी में बाड़ियों की संख्या क्रमश: 3700 एवं 4573 रही। इन बाड़ियों में क्रमश: पौधे विवरण की संख्या की 97464 एवं 61430 थी

जबकि दोनो जिलों में प्रति बाड़ी आय क्रमश: 2900 एवं 4400 रही।

प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण

तालिका क्रमांक – 8

1.क्या नरवा–गरूवा–घुरूवा–बाड़ी योजना के लागू होने के पश्चात् आपके परिवार की आय में वृद्धि हुई हैं ?

क्र.	रायपुर			धमतरी		
	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	72	80%	हाँ	68	75.55%
2.	नही	18	20%	नही	22	24.45%
	योग	90	100%		90	100%

(स्त्रोत:– प्राथमिक समंक)

ग्राफ क्रमांक – 8

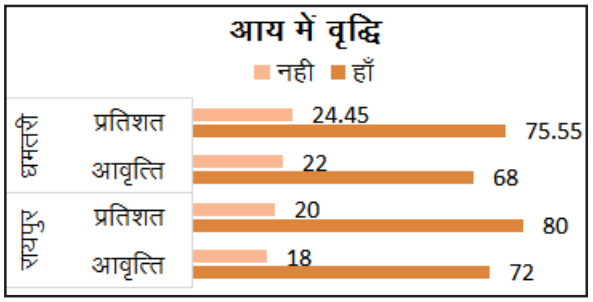

तालिका क्र. 8 के अनुसार रायपुर जिले के 80 प्रतिशत लोग की आय में वृद्धि नरवा–गरूवा–घुरूवा–बाड़ी योजना के लागू होने से हुई है जबकि 20 प्रतिशत लोगों की आय में योजना का प्रभाव नही पड़ा है। वही धमतरी जिलें में 75.55 प्रतिशत लोगों की आय में वृद्धि योजना के आने बाद हुई है जबकि 24.45 प्रतिशत लोगों ने माना कि योजना के आने से उनकी आय में किसी प्रकार की वृद्धि नही हुई हैं।

तालिका क्रमांक – 9

2. क्या नरवा–गरूवा–घुरूवा–बाड़ी योजना प्रारंभ होने के बाद आपकी आजीविका में कोई नया काम जुड़ा हैं ?

क्र.	रायपुर			धमतरी		
	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	63	70%	हाँ	71	78.88%
2.	नही	27	30%	नही	19	21.12%
	योग	90	100%	8273	90	100%

(स्त्रोत:– प्राथमिक समंक)

ग्राफ क्रमांक – 9

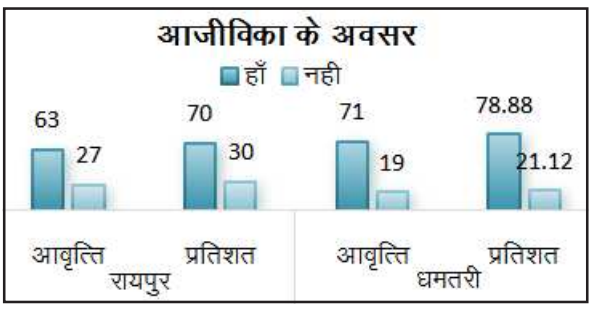

तालिका क्रमांक 9 के अनुसार रायपुर जिले के हितग्राहियों में से 70 प्रतिशत लोगो को योजना के माध्यम से आजीविका के नए अवसर प्राप्त हुए है जबकि 30 प्रतिशत को नवीन अवसर प्राप्त नही हुए उन्हे कृषि कार्य का लाभ प्राप्त हुआ हैं। वही धमतरी जिले में चुने गए हितग्राहियों मे से 78.88 प्रतिशत लोगों को आजीविका के अन्य अवसर प्राप्त हुए हैं। जबकि 21.21 प्रतिशत लोगों ने कृषि कार्य में ही योजना का लाभ प्राप्त किया।

तालिका क्रमांक – 10

3. क्या आपके परिवार की महिलाओं को आर्थिक लाभ मिला ?

क्र.	रायपुर			धमतरी		
	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	58	64.45%	हाँ	67	74.45%
2.	नही	32	35.55%	नही	23	25.55%
	योग	90	100%	8273	90	100%

(स्त्रोत:– प्राथमिक समंक)

ग्राफ क्रमांक – 10

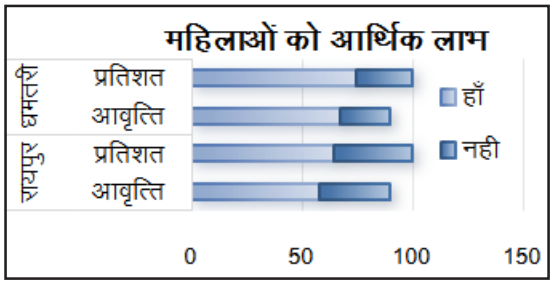

परीकल्पना परीक्षण

क्र.	परिकल्पना	X2	Df	P Value	परिणाम
H_1	नरवा–गरूवा–घुरूवा–बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई है।	0.514	1	>0.05	स्वीकृत
H_2	योजना के माध्यम से प्राप्त आजीविका विविधीकरण के अवसरों में रायपुर तथा धमतरी जिलेंमें अंतर हैं।	1.87	1	>0.05	अस्वीकृत
H_3	नरवा–गरूवा–घुरूवा–बाड़ी योजना ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं।	27.22	1	>0.05	स्वीकृत

निष्कर्ष – अध्ययन उपरांत यह निष्कर्ष सामने आता है कि नरवा–गरूवा–घुरूवा–बाड़ी योजना ने रायपुर एवं धमतरी दोनों जिलों में ग्रामीणों की आय वृद्धि, आजीविका विविधीकरण तथा महिलाओं के आर्थिक सशिक्तकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं। योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ हुई तथा सरकार परिवर्तन के साथ वर्ष 2023 में योजना को समाप्त कर दिया गया। इस 4 वर्ष 11 माह की योजनावधि में योजना से लाखों लोग लाभन्वित हुए। योजना के क्रियान्वयन के दौरान कई चुनौतियाँ जैसे कोरोना महामारी, अल्पावधि, जागरूकता अभियान के लिए समय न मिल पाना, आदि का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी ग्रामीण इस योजना से लाभ प्राप्त कर सके। और योजना को पुन: प्रारंभ करने के सुझाव समंक संकलन के समय ग्रामीणों द्वारा

किया गया। वर्तमान में यह योजना भले ही बंद हो चुकी हैं परंतु ग्रामीण परिवेश से योजना के चारो घटकों नरवा–गरूवा–घुरूवा–बाड़ी को भिन्न नहीं किया जा सकता। योजना के पहले भी ये घटक ग्रामीणों के जीवन का अहम हिस्सा थे। योजना के दौरान इन घटकों को एकीकृत करके ग्रामीण विकास के लिए अथक प्रयास किया गया। योजना के बंद होने के बाद भी नरवा–गरूवा–घुरूवा–बाड़ी को भिन्न नही किया जा सकता।

समस्याएँ :

1. योजना के क्रियान्वयन हेतु अत्यंत ही कम समय 4 वर्ष 11 माह ही मिल पाया।
2. योजना का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों के द्वारा किया जा रहा था। विभागों के बीच समन्वय का अभाव देखा गया।
3. योजना के लिए लोगो को जागरूक कर पाने का बहुत कम समय मिल पाया बहुत से संभावित हितग्राही योजना के लाभ से वंचित रहे।

सुझाव :

1. किसी भी ग्रामीण आर्थिक विकास से संबंधित योजना पर राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव नही पड़ना चाहिए।
2. यदि योजना का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण एक से अधिक विभाग कर रहा हैं तो उनके बीच समन्वय होना आवश्यक हैं।
3. चूँकि नरवा–गुरूवा–घुरूवा–बाड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है इसलिए इस योजना को पुन: प्रारंभ किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन (2024–25), पृ.क्र. (120–144)
2. गुप्ता अरूणेश कुमार (2021), 'छत्तीसगढ़ राज्य की नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना' शोध समागम, अदिति प्रकाशन, वॉल्युम–04 पृ.क्र. (1604–1607)
3. Kothari C.R.And Garg Gaurav (2019) "Research methodology methodsAnd techniques" NewAge international Pvt. ltd. (Delhi), page no. (1-27)
4. Kumar Siddharth,A.K. Gauraha, Sharma Shashank And Bhaskar Shiv (2021)"An EconomicAnalysis of production And marketing of vermicompost in Balod District of Chhattisgarh International Journal of microbiologyApplied sciences, volume - 10, Issue-17, Page no. (532-538)
5. Mangal S.K.And Mangal Shubhra (2019), " Research methodology in Behavioral Science" PHJ learning pvt. ltd. (New Delhi), Page No. (53-70)
6. मुखर्जी रविन्द्रनाथ (2009) 'सामाजिक शोध व सांख्यिकी' विवेक प्रकाशन, जयपुर (राजस्थान), पृ.क्र. (1–12)
7. Mathur Parul (2021), "Narwa, Garuwa, Ghuruwa, Bari Program Development in Chhattisgarh". Shodh Sarita Volume -08, Issue- , page no. (271- 277)
8. मुखर्जी रविन्द्रनाथ (2009) 'सामाजिक शोध व सांख्यिकी' विवेक प्रकाशन, जयपुर (राजस्थान), पृ.क्र. (1–12)
9. सबंल शासन की कल्याणकारी योजनाएँ (2021) जनसंपर्क विभाग (छ.ग.), पृ.क्र. (6–7 एवं 58–65)
10. साहू, तोमेश्वरी (2025) 'छत्तीसगढ़ सुराजी गाँव योजना अंतर्गत गरूवा योजना की भूमिका का अध्ययन' अमोघवर्ता अदिति प्रकाशन रायपुर (छ.ग.), वाल्युम–04, ईशु–04, पृ.सं. (139–144)
11. www.cglive.in (18/02/2025)
12. www.ruralindustries.gov.in (19/02/2025)
13. www.nggb.cg.nic.in (19/05/2025)
14. www.uad.cg.gov.in (21/04/2025)
15. www.cgstate.gov.in (18/04/2025)
16. www.agripostal.cg.nic.in (26/03/2025)
17. www.divert.cg@nic.in (15/03/2025)
18. www.prd.cg.gov.in (29/02/2025)

****